IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

Www.MarwadkaMitra.in

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 UDYAM-RJ-19-0033346

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 23 | अंक 08 | सांचौर, मंगलवार 15 अप्रैल 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

बाल विवाह एवं रोकथाम पोस्टर का किया विमोचन

पाली,। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशों के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला कलक्टर एल एन मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने बाल विवाह रोकथाम पोस्टर का विमोचन किया। जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने बाल विवाह रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों व अधीनस्थ कार्मिको को सतर्क रहते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग अश्विन के पंवार ने बताया कि यदि किसी बच्चे का जबरदस्ती बाल-विवाह किया जा रहा है तो उसकी सूचना चाइल्ड हैल्प लाईन नम्बर 1098 पर देवें।

दौसा जिले में 10 जीएसएस के गठन की स्वीकृति

जयपुर । प्रदेश के सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने दौसा जिले में 10 नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की हैं, जिसके मुताबिक महेश्वरा खुर्द, कुशालपुरा, महाराजपुरा, पटटी किशोरपुरा, जगनेर तर्कान, लाखनपुर, प्रतापपुरा, कीरतपुरा, गोलाडा, कैलाई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन होगा । इसके लिए स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर से प्रथम पांच वर्ष के लिए नि:शुल्क 1500 वर्ग मीटर का भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा।

प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में राज्य सरकार की अनूठी पहल

जयपुर,। बारां जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बारां के मिनी सचिवालय सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया। यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने योजना के सुचारु संचालन के लिए प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपये की राशि देने का निर्णय लिया है।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं । सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में चयनित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गो-लाईव नहीं होने की तिथि तक वित्तीय वर्ष 2025-26 में खरीफ सीजन का ऋण वितरण प्रतिबंधित

210 सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को खरीफ सीजन में नहीं मिलेगा सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत फसली ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले में किसानों को खरीफ बुवाई के लिए सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत फसली सहकारी ऋण नहीं मिलेगा, क्योंकि पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर 30 जनवरी 2025 को जारी निर्देशों की अनुपालना में एक आदेश जारी करते हुए सीसीबी प्रबंध निदेशक ने पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में चयनित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गो-लाईव नहीं होने की तिथि तक वित्तीय वर्ष 2025-26 में खरीफ सीजन का ऋण वितरण प्रतिबंधित कर दिया हैं। साथ ही, सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सीसीबी प्रधान कार्यालय के कंप्यूटर प्रोग्रामर को पैक्स कंप्यूटराइजेशन परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 210 चयनित सहकारी समितियों, जो गो लाईव नहीं हो पाई हैं, उन समितियों की ऋण वितरण से संबंधित एफ.आई.जी. आई.डी को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए निर्देशित किया हैं,

एफ.आई.जी पोर्टल के माध्यम से ऋण वितरण प्रणाली होने के चलते एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर पर सारी एंट्री मैनुअल तौर पर एक-एक करके करनी पड़ रही

गौरतलब हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सरकार की बजट घोषणा के तहत प्रदेश में 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ का ऋण वितरण करने की मंशा पर पानी फेरने की शुरुआत पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना की आड़ की गई हैं। हालांकि केंद्रीय सहकारी बैंकों में नाबार्ड एवं आरबीआई के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सूत्र गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहें हैं, लेकिन नाबार्ड एवं आरबीआई के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत सीसीबी में प्रबंध निदेशकों के पद पर सहकारिता सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं,

945 करोड़ के ऋण वितरण पर कंप्यूटराइजेशन की काली छाया

केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को डिजिटलीकरण करने की कवायद राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं, इस पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण के मामले में जब व्यवस्थापकों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि एफ.आई.जी पोर्टल के माध्यम से ऋण वितरण प्रणाली होने के चलते उन्हें (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) सॉफ्टवेयर पर सारी एंट्री मैनुअल तौर पर एक-एक करके करनी पड़ रही हैं, जिससे समय लग रहा हैं । उनका कहना था कि बैंक को एफ.आई.जी. से डायरेक्ट एंट्री ट्रांसफर कर ऑटोमेटिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे समय के साथ पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य निष्पादित किया जा सकें । जबकि खरीफ सीजन में बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक को 945 करोड़ के फसली ऋण वितरण का लक्ष्य आवंटित किया गया हैं ।

भूल किसकी? भुगतना सिर्फ किसान को

केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सुविधा शुल्क की आड़ में बैंक प्रबंधन की ओर से बैंकडोर नियुक्ति से चयनित व्यवस्थापकों द्वारा केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में कार्य निष्पादित नहीं किया गया, जिसके चलते सीसीबी की ओर से ऋण वितरण प्रतिबंधित होने से राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना से वंचित सिर्फ जिले के किसान ही रहेंगे हालांकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शीर्ष सहकारी बैंक की ओर से केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 41410 पात्र गोपालाकों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य आवंटन किया गया था, लेकिन इसमें भी महज खानापूर्ति कर सरकार की योजना को पंगु बनाने का कार्य सीसीबी प्रबंधन द्वारा किया गया हैं ।

30 फीसदी सहकारी समितियों में पद रिक्त

जिले में 453 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें 30 फीसदी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त पड़े हैं और इनमें से कई व्यवस्थापकों के पास तो 3 से 4 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का अतिरिक्त चार्ज के अलावा सीसीबी की संबंधित शाखा में ऋण पर्यवेक्षक का अतिरिक्त कार्यभार तक मिला हुआ हैं, नेहरू सहकार भवन जयपुर की बिल्डिंग में सहकारिता की नीति एवं पॉलिसी निर्धारित करने वाले अफसरों को जिलों से शायद जानकारी नहीं मिल रही हैं या यह अफसर जानबुझकर सहकारिता विभाग में सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में व्यस्त हैं ?

किसानों के लिए एक अच्छी खबर इस बार झमाझम बरसेगा मानसून

सामान्य से तीन प्रतिशत ज्यादा वर्षा का अनुमान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। किसानों एवं देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होने जा रही है। जून से सितंबर के बीच मानसूनी मौसम के दौरान औसत से तीन प्रतिशत ज्यादा बारिश हो सकती है। इस दौरान संपूर्ण भारत में औसतन लगभग 868.6 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष लगभग 895 मिमी बारिश होने का अनुमान है। मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काइमेट ने अपने ताजा अनुमान में बताया है कि प्रशांत महासागर में न्यूट्रल स्थिति है। ला-नीना बेहद कमजोर हो चुका है और अगले चार महीने के दौरान अलनीनो के विकसित होने की संभावना भी नहीं है। हिंद

महासागर का जलवायु पैटर्न भी अनुकूल दिख रहा है, जो मानसूनी बारिश के लिए मददगार साबित होगा। मानसून में अच्छी बारिश खेती कार्य में सहायक होती है। इसी दौरान खरीफ की फसल की बुआई और रोपाई होती है। भूजल स्तर में भी वृद्धि होती है, जिससे वर्ष भर पेयजल की कमी नहीं हो पाती है। पूर्वानुमान में 96 से 104 प्रतिशत तक बारिश को सामान्य माना जाता है। चार महीने के दौरान 103 प्रतिशत का मतलब है कि अच्छी बारिश होगी। हालांकि, इसमें पांच प्रतिशत तक अंतर आ सकता है। मतलब सामान्य से पांच प्रतिशत कम या ज्यादा बारिश हो सकती है। भारतीय तट पर मानसून कब दस्तक देगा? स्काइमेट का अनुमान है कि 96 प्रतिशत से नीचे जाने का अनुमान बहुत ही कम है। देश के पश्चिमी तट एवं मध्य भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। भारतीय तट पर मानसून कब दस्तक देगा, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है। मगर मानसून का प्रवेश केरल के रास्ते होता है, जहां सामान्य तौर पर एक जून को सक्रिय होता है। फिर धीरे-धीरे दक्षिण भारत के राज्यों से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के सहारे मध्य एवं उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। सबसे अंत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक फैलता है। स्काइमेट ने कोर मानसून मंथ के दौरान कुछ क्षेत्रों में औसत से कम बारिश की भी आशंका जताई है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में मानसून सामान्य रहने वाला है। जून में मानसून की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ला-नीना का असर कुछ दिन तक रह सकता है। जून में औसत से चार प्रतिशत कम बारिश हो सकती है, लेकिन अगले महीने से बारिश रफ्तार पकड़ लेगी। जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में औसत से ज्यादा बारिश होगी। अगस्त में आठ प्रतिशत ज्यादा वर्षा हो सकती है। खेती के लिहाज से यह महीना ज्यादा अनुकूल होता है।

राजीव गांधी सहकार भवन में 17 अप्रैल को आयोजित होगी केंद्रीय सहकारी बैंकों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । *जोधपुर स्थित राजीव गांधी सहकार भवन में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर कार्यालय में 17 अप्रैल 2025 को प्रात: 11.30 बजे जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली एवं सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक की समीक्षा बैठक का आयोजन राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता किया जाएगा । इसके लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.के.नाग की ओर से जारी एजेन्डा अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बिजनेस पैरामिटर्स के साथ राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति एवं भारत सरकार की पैक्स कंप्यूटराईजेशन एवं सहकार से समृद्धि योजना की क्रियान्विति, के अलावा सहकारिता में सहकार अभियान के तहत म्हारों खातों म्हारों बैंक अभियान की क्रियान्विति सहित केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कठिनाईयों के संबंध में सुझाव और विभिन्न वैधानिक मापदण्डों की समीक्षा की जाएगी । हालांकि 8 अप्रैल को सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव ने जोधपुर खंड की संभाग स्तरीय बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया था। जबकि विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि 1 अप्रैल को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में योजनओं की क्रियान्विति पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नाराजगी के पश्चात सहकारिता विभाग की अफसरशाही ए.सी कमरों से बाहर निकली हैं । अब प्रदेश में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन उच्च स्तरीय अधिकारियों की अध्यक्षता में हो रहा हैं, यहां तक कि प्रदेश के सहकारिता विभाग में पहली बार देखने एवं सुनने को मिल रहा हैं कि सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव तक को संभाग स्तरीय मीटिंग का आयोजन कर विभाग की समीक्षा करने की नौबत आन पड़ी हैं ।*

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने आवंटित किए फसली ऋण वितरण के लक्ष्य

ब्याज मुक्त योजना में किसानों मिलेगा 25 हजार करोड़ का फसली सहकारी ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में ब्याज मुक्त योजना के तहत किसानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 25 हजार करोड़ के फसली सहकारी ऋण मुहैया कराने की बजट घोषणा हुई, जिसके क्रम में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से आज बैंकवार रबी एवं खरीफ सीजन के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया हैं । इस संबंध में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक ने समस्त केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजकर निर्देशित किया हैं कि यदि बैंक द्वारा फसलवार निर्धारित कुल ऋण वितरण के लक्ष्यों में कमी या अधिकता रहती है तो बैंक अपने स्तर पर कुल ऋण वितरण के लक्ष्य के अंतर्गत ही खरीफ एवं रबी फसल हेतु निर्धारित लक्ष्यों को हस्तांतरित कर सकते हैं, ताकि 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति' के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में ऋण वितरण करना सुनिश्चित किया जा सके तथा राज्य सरकार द्वारा श्रेणीवार आवंटित ब्याज अनुदान सहायता के लिए जारी राशि का पूर्ण उपयोग हो सके ।

सीसीबीवार लक्ष्य हुए निर्धारित

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से इस वि8ीय वर्ष 2025-26 के तहत, अजमेर सीसीबी को 672 करोड़, अलवर सीसीबी को 1127 करोड़, बांसवाड़ा सीसीबी को 461 करोड़, बारां सीसीबी को 549 करोड़, बाड़मेर सीसीबी को 1240 करोड़, भरतपुर सीसीबी को 532 करोड़, भीलवाड़ा सीसीबी को 1357 करोड़, बीकानेर सीसीबी को 899 करोड़, बूंदी सीसीबी को 701 करोड़, चित्तौड़गढ़ सीसीबी को 1285 करोड़, चूरू सीसीबी को 543 करोड़, दौसा सीसीबी को 566 करोड़, डूंगरपुर सीसीबी को 330 करोड़, हनुमानगढ़ सीसीबी को 1313 करोड़, जयपुर सीसीबी को 1905 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया है। इसी प्रकार जैसलमेर सीसीबी को 540 करोड़, जालोर सीसीबी को 805 करोड़, झालवाड़ सीसीबी को 954 करोड़, झुंझुनूं सीसीबी को 838 करोड़, जोधपुर सीसीबी को 870 करोड़, कोटा सीसीबी को 894 करोड़, नागौर सीसीबी को 679 करोड़, पाली सीसीबी को 979 करोड़, सवाई माधोपुर सीसीबी को 660 करोड़, सीकर सीसीबी को 1406 करोड़, सिरोही सीसीबी को 281 करोड़, श्रीगंगानगर सीसीबी को 1156 करोड़, टोंक सीसीबी को 670 करोड़ तथा उदयपुर सीसीबी को 788 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

तखतगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड तखतगढ़

एक सब के लिए, सब एक के लिए

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

गोपालसिंह अध्यक्ष
छगनलाल उपाध्यक्ष
नरेन्द्रसिंह व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए' सब '

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

अन्नदाता किसान का समान और आर्थिक सुरक्षा हमारा ध्येय - भजनलाल शर्मा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। श्रीगंगानगर स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय स्लिप प्रदान कर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद का विधिवत शुभारंभ कर किसानों एवं व्यापारियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान को पूरा समान और सुरक्षा के साथ ही उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना हमारा ध्येय है। हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान समय पर सुनिश्चित कर रही है। इसी दिशा में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2025-26 में सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 हजार 950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है तथा इस साल 13 लाख 22 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा है। इसी तरह सरकार 5 हजार 650 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी के आधार पर 5 लाख 46 हजार मीट्रिक टन चना की खरीद करेगी। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

श्रीगंगानगर स्थित नई धान मंडी में सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

किसानों की समृद्धि के लिए कार्य कर रही राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बोनस को बढ़ाकर 150 रुपये एवं किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है। साथ ही, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लेकर वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

हमारी सरकार ने एमएसपी खरीद की सीमा को बढ़ाया

श्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022-23 में सरसों का एमएसपी 5 हजार 50 रुपये था, जिसमें हमारी सरकार ने 900 रूपये तक की बढ़ोत्तरी की है। साथ ही एमएसपी पर खरीद के लिए प्रति किसान 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने सवा साल के समय में अब तक 4 लाख 85 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की है जबकि पिछली सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में केवल 5 लाख 53 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की थी। साथ ही हमारी सरकार ने मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5 हजार 850 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार 783 रुपये प्रति क्विंटल किया है।

फसली ऋणों की भुगतान तिथि बढ़ाने से लाभान्वित होंगे 2.19 लाख से अधिक किसान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्प्स के माध्यम

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक फाइल

से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून, 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। श्री दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता।

पैक्स कंप्यूटरीकृत की आड़ में प्रतिबंध की जा रही सबसे बड़ी योजना..!

प्रदेश में साहुकार प्रथा से निजात दिलाने के लिए गांवों में किसानों के सहयोग से गठित की गई ग्राम सेवा सहकारी समितियां आज एआई युग में अपने मूल व्यवसाय से दिन-ब-दिन पिछड़ती नजर आ रही हैं, एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एआई युग में कंप्यूटरीकृत करने की पहल की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत करने की होड़ मची हुई हैं । इसके लिए सहकारिता विभाग के अधिकारी जी-जान से जुटे हुए हैं, यह अधिकारी आंख मूंदकर प्रदेश में 35 लाख किसानों से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी सहकारिता विभाग की सबसे बड़ी ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना को प्रतिबंधित कर पलीता लगाने जैसे कार्य करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं, जबकि पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में सबसे बड़ा बाधक एफ.आई.जी पोर्टल की समीक्षा करने के बजाए बैंकिंग प्रतिस्पर्धा के दौर में भी इस एरर प्रणाली वाले एफआईजी पोर्टल को बंद करने के बजाए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर से सहकारी समितियों की साख को बटा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही हैं और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के एफआईजी पोर्टल की पद्धति से ऋण व्यवसाय पॉलिसी के संचालन में हां से हां मिलाकर मौन स्वीकृति दी जा रही हैं । आज गांवों में छोटे-छोटे स्तर पर उत्पादक प्रक्रिया में लगे लोगो को आपसी सहयोग के आधार पर प्रोत्साहित कर उनके आर्थिक उन्नयन का ढांचा सहकारी समितियां अब पूरी तरह चरमरा गई हैं, एफआईजी पोर्टल ने कृषि ऋणदात्री सोसायटी के ऋण व्यवसाय की जड़ों को पूरी तरह खोखला कर दिया हैं, एफआईजी पोर्टल की आड़ में सहकारी समितियों से जो लूट का खुला खेल हुआ है, उसे सब जानते हैं, पर किसी भी सरकार ने इन पर सख्त कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई तो उसके पीछे सीधी वजह वोट बैंक की सियासत हैं। एफआईजी पोर्टल के जरिए नाबार्ड से समय पर पुनर्वित्त लेने और सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की बात की गई थी, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सहकारी समितियां से लेकर केंद्रीय सहकारी बैंकों तक के हाल जस के तस है। ऐसा नहीं है कि सहकारिता के त्रि-स्तरीय ढांचे की सबसे छोटी इकाई पैक्स में कोई खामी है। खराबी तो वर्तमान में एफआईजी पोर्टल की ऋण वितरण पॉलिसी संचालन में हैं । आज पूरी पारदर्शिता के साथ सहकारी समितियों में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने की आवश्यकता है । क्योकि एफआईजी पोर्टल की ऋण वितरण पॉलिसी की वजह से सहकारी समितियां इस समय ऋण व्यवसाय के लिए नाजुक दौर से गुजर रही हैं ।

मुद्रा ऋण की परिवर्तनकारी भूमिका

आज, मुद्रा ऋण असंगठित और ऋण सुविधा से वंचित क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय जीवन रेखा बन गए हैं तथा आजीविका सृजन और आर्थिक विकास को गति देते हैं। एक दशक पूरा होने पर, इसका प्रभाव भारत भर में अर्ध-शहरी, ग्रामीण और दूरदराज की अर्थव्यवस्थाओं के परिवर्तन से स्पष्ट होता है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, पीएमएमवाई योजना ने 52 करोड़ खातों के लिए 33 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण का संवितरण किया है, जिससे चित समुदायों को काफी फायदा हुआ है

अशोक चंद्रा एमडी और सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक

भारत की आर्थिक प्रगति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई की सफलता के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र, न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार के रूप में कार्य करता है, बल्कि रोजगार सृजन और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षमता की पहचान करते हुए, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई की शुरुआत की थी, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों एमएसई को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल है। इस योजना को लोकप्रिय रूप में मुद्रा ऋण के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यम भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य का मूल है। आज, मुद्रा ऋण असंगठित और ऋण सुविधा से वंचित क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय जीवन रेखा बन गए हैं तथा आजीविका सृजन और आर्थिक विकास को गति देते हैं। एक दशक पूरा होने पर, इसका प्रभाव भारत भर में अर्ध-शहरी, ग्रामीण और दूरदराज की अर्थव्यवस्थाओं के परिवर्तन से स्पष्ट होता है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, पीएमएमवाई योजना ने 52 करोड़ खातों के लिए 33 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण का संवितरण किया है, जिससे वंचित समुदायों को काफी फायदा हुआ है। उल्लेखनीय रूप से, इनमें से लगभग 50 प्रतिशत ऋण एससी/एसटी/ओबीसी उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गए हैं, जबकि 68 प्रतिशत ऋण से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया गया है, जिससे वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका मजबूत हुई है। छोटे व्यवसायों को सक्षम बनाना, आजीविका को सशक्त बनाना, मुद्रा ऋण योजना की अवधारणा, तीन श्रेणियों-शिशु 50,000 रुपये तक के ऋण, किशोर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण और तरुण 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण के तहत बिना कोई चीज गिरवी रखे वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। सफल एमएसई की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अक्टूबर 2024 में एक नई श्रेणी तरुण प्लस की शुरुआत की, जिसके तहत मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई। यह संरचना युक्त दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यवसायों को विभिन्न विकास चरणों में उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त हो। छोटे व्यवसाय से जुड़े कई लोगों, जैसे स्ट्रीट वेंडर, कारीगर और ग्रामीण उद्यमियों के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच एक चुनौती थी। मुद्रा ऋण ने बैंकिंग अंतर को दूर करके और नए विकास के अवसरों को खोलकर छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार करने वालों, जैसे किराना स्टोर मालिक, कारीगर और टियर 2 शहरों के तकनीकी स्टार्टअप को सशक्त बनाया है। मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से, पंजाब नेशनल बैंक ने 64.50 लाख से अधिक ऋण खातों के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और वित्तपोषण से वंचित लोगों को वित्तपोषित करने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। महिला उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को विकसित करना मुद्रा ऋण के संवितरण का एक उल्लेखनीय रुझान महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी है। मुद्रा लाभार्थियों में से लगभग 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो उनके बीच वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, हरियाणा की शीला देवी, जो पहले घर पर ही एक छोटे सी व्यवस्था तक सीमित थीं, ने पीएनबी से शिशु मुद्रा ऋण की मदद से अपनी फर्नीचर की दुकान का विस्तार किया है और अब पांच अन्य महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, जिससे उनके समुदाय में रोजगार और आत्मनिर्भरता का क्रमिक प्रभाव पैदा हो रहा है। विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में देश भर में इसी तरह की सफलता की कहानियां देखी जा सकती हैं। निर्बाध डिजिटल ऋण समाधानों के साथ व्यवसाय विकास को प्रोत्साहन देना वित्तीय समावेशन में वित्तीय संस्थानों का बढ़ता योगदान, सरलीकृत ऋण प्रक्रियाओं और अभिनव डिजिटल समाधानों से संचालित हो रहा है। उदाहरण के लिए, 2023 के प्रारंभ में शुरू की गई पीएनबी ई-मुद्रा योजना, शुरू से अंत तक डिजिटल सुविधा प्रदान करती है, जिसके तहत ग्राहक पूरी तरह दस्तावेज रहित प्रक्रिया के माध्यम से। लाख रुपये तक के मुद्रा ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी बैंक शाखा की भागीदारी नहीं होती है। इस प्लेटफॉर्म से 14,152 लाभार्थियों को 136 करोड़ रुपये की तत्काल ऋण स्वीकृति सुनिश्चित हुई है। पीएनबी ने 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच ऋण की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए डिजी एमएसएमई ऋण योजना शुरू करके अपने डिजिटल पेशकश को और मजबूत किया है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए समय पर और परेशानी मुक्त ऋण पहुंच सुनिश्चित हुई है। एमएसई विकास के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करना। यह स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पर मुद्रा योजना ने समय पर और किफायती ऋण प्रदान करने, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने तथा देश भर में आय सृजन और रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हुए, बेहतर डिजिटल ऋण, अधिक वित्तीय साक्षरता और मजबूत ऋण सहायता व्यवस्था को शामिल करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण, एमएसई की सफलता को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होगा, ताकि प्रत्येक उद्यमी की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार किया जा सके। निष्कर्ष के तौर पर, यह कहा जा सकता है कि मुद्रा योजना केवल वित्तपोषण से संबंधित नहीं है। यह उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के बारे में भी है, जो भारत के आर्थिक इंजन को गति देती है। सही वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ, आज के छोटे व्यवसाय कल की आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे।

बालोतरा जिले में सहकारिता विभाग पंजीयक के पत्र के बावजूद जारी नहीं हो रहा आदेश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर संभाग में जालोर, सिरोही, बाड़मेर, फलौदी जिला कलेक्टरों ने कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने से पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने के संबंध में जारी किया आदेश, जबकि बालोतरा जिले में आदेश के अभाव में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की राशि बकाया होने के बावजूद निरंतर कृषि भूमि की हो रहा हैं रजिस्ट्री एवं इंतकाल का कार्य

बालोतरा । जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सामने अल्पकालीन फसली ऋण की वसूली को लेकर एक ओर समस्या खड़ी हो गई है। जहां यह ग्राम सेवा सहकारी समितियां कृषि भूमि का रहन किए बिना ही किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण एवं पशुपालन के लिए कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा हैं । लेकिन इन समितियों के कार्यक्षेत्र से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों द्वारा किसी स्थिती में कृषि भूमि का बेचान कर दिया जाता है। वही ऋणी की मृत्यु होने पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करवाया जाता हैं । जिससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा वितरित ऋण की वसूली नहीं हो पाती है। अब जब जोधपुर संभाग के जालोर, सिरोही, बाड़मेर, फलौदी जिलों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने के पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से अदेय प्रमाण पत्र या बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने के पश्चात ही कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलेक्टरों द्वारा दिए गए हैं, जबकि इस मामले में सहकारिता विभाग पंजीयक मंजू राजपाल की ओर से 28 जनवरी 2025 प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया था । वही जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने बालोतरा जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मामला संज्ञान में लाया था, लेकिन जिला कलेक्टर की ओर से आदेश जारी नहीं किया जा रहा हैं । जबकि प्रदेश के अनेक जिलों के जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज करने से पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से बकाया नहीं प्रमाण लेने के बाद आगामी कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए हुए हैं, जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बकाया ऋण वसूली में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

मैली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मैली

एक सब के लिए सब एक के लिए

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

गणपत सिंह
अध्यक्ष

पारसराम मेघवाल
व्यवस्थापक

वालाराम चौधरी - उपाध्यक्ष

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए' है

केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्मिकों ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सवाईमाधोपुर, केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाईमाधोपुर के कार्मिकों ने प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत को ज्ञापन देकर बैंक के कम्प्युटर प्रोग्रामर को नियम विरुद्ध वरिष्ठ प्रबंधक पद पर की गई पदोन्नति को निरस्त करने तथा विभागीय रिव्यू डी.पी.सी. वर्षवार के आधार पर पदोन्नति बैठक आयोजित किए जाने की मांग की है। कालीचरण शर्मा (प्रबन्धक), सुभाष चन्द बबेरवाल (प्रबन्धक) आदि केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्मिकों ने ज्ञापन में बताया कि सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार प्रबन्धक पद से ही 100 प्रतिशत वरिष्ठ प्रबन्धक पद पर पदोन्नति की जाएगी। इसके बावजूद नियमों को दरकिनार करते हुए कम्प्यूटर प्रोग्रामर उपेन्द्र कुमार शर्मा प्रबन्धक (प्रशासन) के पद पर काबिज है। इनके द्वारा सहकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान जयपुर के पदों से फेरबदल करते हुए वर्तमान में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद को कभी रिक्त तो कभी भरा हुआ बताया कर प्रबंधक (प्रशासन) पद का दुरुपयोग किया है। शर्मा को स्टोर प्रभारी बनाया हुआ है जो व्यक्तिगत हितों में नियमों की अवहेलना कर कतई अनुचित है। कम्प्यूटर प्रोग्रामर एक टेक्नीकल पद है। बैंकिंग प्रणाली में काम करने का अनुभव नहीं होने से भविष्य मे बैंक को बहुत बडी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। जो बैंक की साख को कभी भी डूबो सकता है। ऐसे में कम्प्युटर प्रोग्रामर से प्रबंधक (प्रशासन) पदोन्नत हुए उपेन्द्र कुमार शर्मा की पदोन्नति रद्द की जाए।

शहरी एरिया में संचालित बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति आज एक सफल मिनी बैंक, हर साल सदस्यों को मिलता 9 फीसदी लाभांश और 21 फीसदी बोनस

सफलता की कहानी....

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

कोटाः संयुक्त राष्ट्र इस साल को सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहा है. भारत में कोऑपरेटिव का महत्व और चलन खासा मायने रखता है. इस बीच कोटा जिले में स्थित बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति (जीएससीसी) प्रदेश में सफलता की नई कहानी लिख रहा है. एक सफल मिनी बैंक के रूप में जीएससीसी बोरखेड़ा न केवल अपनी अलग पहचान बना रहा है, बल्कि लोगों को अच्छा मुनाफा भी दे रहा है. कोटा में अभी कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां कम कर रही हैं. कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियां शहर की सीमा में आने के चलते बंद हो गई, लेकिन बोरखेड़ा में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति ने नया उदाहरण सेट किया है. ग्रामीण एरिया खत्म होने के चलते यह शहरी एरिया में आ गई थी. आज ये एक सफल मिनी बैंक है. इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि राजस्थान ही नहीं देश में सबसे अधिक लाभांश और बोनस देने वाली संस्थानों में उनकी जीएससीसी भी शामिल है. उन्होंने कहा कि अब मिनी मार्ट भी खोलने जा रहे हैं, यह भी देश में कुछ संस्थाएं ही संचालित कर रही हैं. जीएससीसी बोरखेड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतराम मीणा का कहना है कि उनके मिनी बैंक की तीन ब्रांच संचालित हैं. इसमें पहले बोरखेड़ा, दूसरी काला तालाब और तीसरी ब्रांच इंदिरा गांधी नगर डीसीएम में है. तीनों जगह पर करीब 10,000 सदस्य मिनी बैंक के हैं. इनमें 62 करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि जीसीसी में कुल 110 करोड़ रुपए जमा हैं. इसमें से 50 करोड़ रुपए लोन के रूप में लोगों को बांटे हुए हैं. चेतराम मीणा ने बताया कि इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य केवल इस इलाके के रहने वाले लोग ही बन सकते हैं. हर साल सदस्यों को लाभांश 9 फीसदी और बोनस 21 फीसदी मिलता है, जो कि 30 फीसदी के आसपास होता है. ये राजस्थान ही नहीं देश की कुछ ही संस्थाएं दे रही हैं. चेतराम मीणा का कहना है कि जीएससीसी व्यवसाय बढ़ाने के लिए फिलहाल बारां रोड पर 11,600 स्क्वायर फीट एरिया में निर्माण करवा रही है. इसमें 500 मीट्रिक टन का गोदाम और खरीद केंद्र स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा एक सुपर मार्केट भी बनाया जा रहा है. पैकिंग यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर भी यहां पर बनाया जाएगा. पैकिंग यूनिट में सुपरमार्केट में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट को भी पैक किया जाएगा.

विकास का बेहतर उदाहरण

सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कोटा के प्रबंध निदेशक बलविंदर सिंह गिल का कहना है कि ग्राम बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति का मिनी बैंक के रूप में रूपांतरण सहकारिता की सक्सेस स्टोरी का आदर्श उदाहरण है. यह कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान में सफलता की कहानी के रूप में अलग स्थान रखती है. उन्होंने बताया कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तब बोरखेड़ा शहर से अलग ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला किसान प्रधान एरिया था. समय के साथ शहर का विस्तार हुआ और इस पूरे क्षेत्र से किसान और जमीन समाप्त हो गई. शहरीकरण इस एरिया में हो गया. इस संस्थान ने अपने आपको लोगों की सेवा करने वाली सक्सेसफुल मिनी बैंक के रूप में रूपांतरण किया और आज कोटा में नई कहानी लिख रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों यह भव्य मिनी सरकारी सुपरमार्केट व मार्ट उपभोक्ता ओं के लिए लेकर आ रहा है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी कई तरह के काम करेगा. सहकारिता के माध्यम से कम्युनिटी डेवलपमेंट इस संस्था ने किया है.

बैंक की तरह पूरा सिस्टम

कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां के खिलाफ गबन, घपले और घोटाले की शिकायतें हैं, हालांकि बोरखेड़ा जीएससीसी में ऐसा नहीं है. अध्यक्ष जानकी लाल गोस्वामी का कहना है कि उनके यहां पर फिक्स डिपाजिट, आरडी, स्मॉल सेविंग और सेविंग व करंट अकाउंट भी खोले जा रहे हैं. सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य के रूप में ही बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं. उनका यह भी कहना है कि स्मार्ट सेविंग्स का रोज कलेक्शन का भी काम उनका है. इससे छोटा व्यापार करने वाले लोगों को भी मदद मिलती है. उनकी रोज की बचत जमा के रूप में बैंक तक पहुंच जाती है. इसके अलावा हम कृषि, सैलरी, व्यावसायिक मॉर्टगेज, पर्सनल और वाहन लोन भी दे रहे हैं. साथ ही केश क्रेडिट कार्ड लिमिट भी बनाते हैं. उन्होंने कहा कि बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम पर काम कर रहा है.

1954 में स्थापना, 30 साल पहले खोला बैंक

जीएससीसी बोरखेड़ा के अध्यक्ष जानकी लाल गोस्वामी का कहना है कि ग्राम सेवा सरकारी समितियां का काम उसके सदस्यों से जुड़ा ही व्यापार करना है. यह गांव में स्थित रहती है और ज्यादातर किसान जुड़े होते हैं. ऐसे में किसानों को खाद - बीज और भंडारण की व्यवस्था उपलब्ध कराना इनका प्राथमिक कार्य रहता है. इसके अलावा कृषि यंत्र और लोन भी किसानों को देती है. उन्होंने बताया कि बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना 1954 में हुई थी. बोरखेड़ा का एरिया आबादी में परिवर्तित हो गया और यहां पर अधिकांश जमीन पर प्लॉटिंग कट गई और लोगों ने मकान बना लिए थे. ऐसे में न तो यहां किसान थे और न जमीन थी. ऐसी स्थिति में बोरखेड़ा जीएससीसी को बंद करना पड़ता, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए इसे मिनी बैंक का रूप दिया गया. मिनी बैंक 1994 में शुरू किया गया, आज ये काफी सफल है.

केंद्र व राज्य सरकार से मिला अवार्ड

जीएससीसी बोरखेड़ा के लाभ की बात की जाए तो साल 2023 -24 में 2.40 करोड़ के आसपास था. बीते सालों में भी 2 करोड़ से ज्यादा मुनाफा रहा है. इसी में से सदस्यों को बोनस और लाभांश दिया जाता है. कर्मचारियों को सैलरी और अन्य खर्च भी इसी से होते हैं. इसी में से समुदाय के विकास के लिए सरकारी स्कूल या अन्य जगहों पर भी राशि दी जाती है. यह राशि लगातार बढ़ती रहती है और बीते साल यह 30 लाख रुपए थी. संस्था को साल 2018 में केंद्र सरकार और 2020 में राज्य सरकार से भी अवार्ड मिल चुका है.

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं। समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है। अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं।

नाम / संस्था का नाम..

ग्राम.................... पोस्ट....................

तहसील.................... जिला....................

फोन.................... पिन कोड....................

राशि (रुपए) .... बैंक का नाम....................

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134

Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका, भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

सहकार से समृद्धि की भावना के साथ कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता- भजनलाल शर्मा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है। श्री शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कॉपरेटिव कोड लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में भी 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण की घोषणा की गई है। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, शासन सचिव पशुपालन श्री समित शर्मा, प्रबंध निदेशक राजफेड श्री टीकम चन्द बोहरा, प्रबंध निदेशक आरएसएलडीबी श्री जितेन्द्र प्रसाद सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

खरीफ-2024 में दलहन और तिलहन की 4700 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0 की ओर से खरीफ सीजन 2024 में दलहन और तिलहन जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन की 4 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की गई, जिसमें मूंगफली की 4 लाख 38 हजार 800 मेट्रिक टन से भी अधिक की रिकॉर्ड खरीद की गई। साथ ही, रबी सीजन 2025-26 के लिए सरसों और चने की खरीद हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर किसानों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए। पात्र किसानों को सहकारी बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों और ग्रामीणों के अधिक से अधिक बचत खाते सहकारी बैंकों में

बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सुनिश्चित

श्री शर्मा ने सहकारिता विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के भण्डारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों का योजनाबद्ध ढ़ंग से भण्डारण सुनिश्चित हो, ताकि इनका अधिकतम उपयोग लिया जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के 1 लाख गोपालक परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बजट 2025-26 में इन परिवारों की संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार कर दी गई है। साथ ही, इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाकर आगामी वर्ष से 9 हजार प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है।

सहकार भारती की बाड़मेर जिला कार्यकारिणी घोषित : अक्षयदान जिला अध्यक्ष निर्वाचित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले में सहकार भारती की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया । इसमें जिला अध्यक्ष पद पर अक्षयदान, उपाध्यक्ष पद पर तगसिंह भाटी, महामंत्री पद पर अशोक दर्जी, जिला प्रमुख पद पर भैराराम जांगिड़, कोषाध्यक्ष पद पर हरीश दर्जी, संगठन प्रमुख पद पर जुझारसिंह परमार, महिला प्रमुख पद पर श्रीमती झीमो देवासी, संपर्क प्रमुख पद पर विक्रमसिंह, प्रचार प्रमुख पद पर गुलाबराम मुंशी, मीडिया प्रमुख पद पर कृष्णा रामावत, कार्यालय प्रमुख पद पर महेंद्र गोयल, प्रशिक्षण प्रमुख पद पर मनोहरसिंह, पैक्स प्रमुख पद पर काछबदान, जिला प्रभारी पद पर हरीश सोलंकी को निर्वाचित किया । इसके पश्चात जिला कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अक्षयदान का माला पहनाकर बहुमान किया गया और सदस्यों द्वारा उन्हे बधाई दी गई । गौरतलब हैं कि सहकार भारती एक संगठन है जो सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करता है।

सांतपुर वृहत कृषि बहुउदेशीय सहकारी समिति आंकरा भट्टा की वार्षिक आमसभा संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । जिले की सांतपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति आकराभट्टा की स्थगित वार्षिक आमसभा वित्तीय वर्ष 20222-23, 2023-24 का आयोजन आज समिति अध्यक्ष श्रीमति नयना बेन बारोट की अध्यक्षता में चामुण्डा माता मंदिर में किया गया । इस दौरान समिति अध्यक्ष एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्यों ने सम्मानित सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया । समिति व्यवस्थापक अफजल खान ने गत आमसभा वर्ष 2021-22 की पुष्टि की, उसके पश्चात वर्ष 2022-23, 2023-24 के लेखो की पुष्टि, वार्षिक बजट 2022-23, 2023-24 की पुष्टि, अनुमानित बजट वर्ष 2024-25 की स्वीकृति जारी करने के उपरांत आगामी वर्ष 2024-25 के वार्षिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्त की गई । इस दौरान संचालक मंडल सदस्य हरीशंकर उपाध्याय, किरण बोहरा, ललिता आर्चाय, अचलाराम कुमावत, ग्यारसाराम तथा समिती सदस्य रामलाल कुम्हार, पुखराज कीर, गणेश आर्चाय, जितेन्द्र बारोट, तेजसिंह देवडा, भोपाल सिंह पुरोहित, बिरेन पटेल,, नासीर खान, वागाराम चौधरी, प्रकाश आर्य, हिमांशु त्रिवेदी, केतन पुरोहित, अजय वाला, सुरज कुमार बंजारा सहित समिति कर्मचारी उपस्थित रहें

खाली भवन किराये पर देने का प्रस्ताव

आमसभा की कार्यवाही के दौरान सांतपुर गांव के क्षेत्रीय किसानों ने समिति हित में अनेक प्रस्ताव उठाएं, जिसमें समिति कार्यालय पर खाद-बीज भंडार खोलने के साथ, समिति में कस्टम हायरिंग केंद्र के टैक्ट्रर की लागत दर निर्धारित कर रियायती दर पर किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा वर्तमान में समिति के खाली पड़े भवन को किराये पर देने का निर्णय आमसभा में प्रस्ताव पारित कर लिया गया । साथ ही, समिति व्यवस्थापक अफजल खान ने समिति काश्तकारों, सदस्यों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया है।

वसूली के लिए अब तक 185 नोटिस किए गए जारी

जालोर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों से नाम पृथक करवाने के लिए 30 अप्रेल तक 'गिव-अप अभियान' चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में अब तक 185 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले में अब तक 4806 परिवारों एवं 16120 सदस्यों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन किए हैं तथा 1238 परिवारों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट से आवेदन किए।

यूनियन की आमसभा संपन्न

सहकार नेता आमेरा ने हनुमानगढ़ सीसीबी में राज्य सरकार की ओर से बकाया 35 करोड़ पर जताई चिंता

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

हनुमानगढ़ । ऑल राजस्थान राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन एवं ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की हनुमानगढ़ जिला यूनिट की आमसभा का आयोजन जिला अध्यक्ष रमेश कुमार दत्ता एवं सरंक्षक रामकुमार सहारण की संयुक्त अध्यक्षता में होटल नारंग में हुआ । जिसमें ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन एवं ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, इस दौरान उनके साथ अपेक्स बैंक यूनियन अध्यक्ष राकेश गुर्जर, दिलीप सिंह जादम, अभिषेक रायजादा, विनोद कुमार मीणा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया । सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने आमसभा को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 व 2019 में की गई सहकारी ऋण माफी की एवज में प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को देय बकाया ब्याज के 750 करोड रूपये का भुगतान करने की मांग करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश से राज्य सरकार की तरफ बकाया राशि का शत-प्रतिशत प्रोविजन करने से इसी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सीआरएआर निर्धारित वित्तीय मानदण्ड 9 प्रतिशत के स्तर से नीचे चला जायेगा। जिससे सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होकर अधिकांश बैंक हानि में आ जायेगें। वही हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक का राज्य सरकार में बकाया 35 करोड़ रूपये का प्रावधान करने से हनुमानगढ़ बैंक का सीआरएआर 8 प्रतिशत के साथ बैंक हानि में आ जायेगा। इस दौरान हनुमानगढ़ जिला सचिव दिनेश आरोड़ा, शैलेन्द्र गुप्ता, विनोद लोहिया, रमेश सैनी, अनिल विश्नोई, सीमा सोलंकी, कल्पना मीणा, रमेश स्वामी, राकेश गुर्जर व दिलीप सिंह जादम यूनियन प्रतिनिधियों ने भी सम्बोधित करते हुए सहकारी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों को सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता, सुरक्षा तथा कार्मिक हितों के लिए यूनियन के साथ एकजुटता व सक्रियता के लिए आह्वान किया। अंत में अध्यक्ष रमेश कुमार दत्ता द्वारा उपस्थित कर्मचारियों एवं अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित कर सभा का समापन किया गया ।

सहकारी बैंकों की छवि हो रही खराब

आमसभा को संबोधित करते हुए सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा

सहकार नेता आमेरा ने वाणिज्यिक बैंक एवं ग्रामीण बैंकों के मर्जर की तरह जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंक में समामेलित कर टू-टीयर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था राज्य में लागू किया जाना समय की मांग बताते हुए सहकारी बैंकों में प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक सक्षमता के लिए रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्ड नीति फिट एण्ड प्रोपर के तहत योग्य अधिकारी एम.डी. लगाने की आवश्यकता, के साथ सहकारी बैंकों की स्टाफ स्ट्रेन्थ ख्क में निर्धारित की गई थी जिसकी वर्तमान बैंकिंग सेवा, सुविधाएं व मशीनीकरण के परिपेक्ष में दुबारा समीक्षा कर बढ़ाये जाने की आवश्यकता भी जताई हैं । वही आमेरा ने क्म्वें वेतन समझौते के लम्बित मुद्दों का वित्त विभाग द्वारा निस्तारण कर जेएआईआईबी/सीएआईआईबी की वेतन वृद्धि का लाभ यथावत जारी किए जाने, सहकारी बैंकों में शाखाओं एवं पैक्स स्तर पर प्रभावी निरीक्षण, नियंत्रण एवं अनुशासन के लिए सीसीबी में फिल्ड कार्य के लिए ऋण पर्यवेक्षक पदों की उपयोगिता को देखते हुए बैंक में ऋण पर्यवेक्षक पद बहाल करने, सहकारी बैंकों में कार्मिकों की प्रभावी स्थानांतरण नीति लागू करने और सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन एवं आरजीएचएस चिकित्सा सुविधा लागू किये जाने की मांग दोहराई हैं । साथ ही, आमेरा ने कहा कि शाखाओं एवं पैक्स में हो रहे गबन, वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से सहकारी बैंकों की छवि खराब हो रही है।

सहायक व्यवस्थापकों को मिलेगा सोसायटी में लेन-देन का अधिकार

अजमेर जिले की सहकारी समितियों में कार्य बहिष्कार समाप्त

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

तीन सप्ताह कार्य बहिष्कार के पश्चात वापिस ऋण वितरण एवं वसूली कार्य में लगे अजमेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक, बैंक ने कुछ शर्तो के साथ वित्तीय अधिकार देने पर जताई सहमति

कार्य बहिष्कार समाप्त करने के उपरांत सीसीबी प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए

अजमेर । जिले में पिछले तीन सप्ताह से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों द्वारा ऋण वितरण एवं ऋण वसूली के कार्य का बहिष्कार किया जा रहा था, इसको लेकर कल व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक संघर्ष समिति अजमेर के अध्यक्ष एवं केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर के मध्य वार्ता होने के उपरांत सहायक व्यवस्थापक को सोसायटी में लेन-देन का अधिकार देने पर सहमति बनी, हालांकि इसके लिए 5 मुख्य शर्ते निर्धारित की गई हैं, जिसमें वित्तीय अनियमितता, अपराधिक प्रकरण में दोषी न होने सहित संचालक मण्डल बोर्ड एवं संबंधित शाखा प्रबंधक की सहमति के साथ लेन-देने के लिए समिति स्तर से प्रस्ताव भिजवाने, के साथ सहकारिता विभाग पंजीयक की ओर से निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का धारक तथा 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्ति होने की अनिवार्यता के अलावा 10 हजार की नकर प्रतिभूति के साथ 3 लाख की फिडिलिटी गारंटी और दो व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति तीन लाख रुपए की व्यक्तिगत जमानत तस्दीक हैसियत शुदा तथा चार्ज लेने वाले सहायक व्यवस्थापक की तस्दीकशुदा सम्पत्ति समिति के अध्यक्ष की निजी गारन्टी की अनिवार्यता की शर्त निर्धारित की गई हैं, इसके साथ ही, व्यवस्था की पूर्णतः अस्थाई बताया गया हैं, यह व्यवस्था स्क्रीनिंग शुदा व्यक्ति या नवीन नियुक्तियां होने तक के लिए उपलब्ध रहेगी । जिसके लिए शपथ पत्र भी लिया जाएगा । अब ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक पुनः अपने काम पर लौट गए है। वही व्यवस्थापक संघर्ष समिति द्वारा बैंक प्रशासन का आभार भी प्रकट किया गया है।

विकास की कसौटी पर पूरी तरह खरी नहीं देश की एक भी ग्राम पंचायत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों को नौ थीम में एकीकृत कर पंचायतीराज मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए काम शुरू किया। तमाम योजनाएं चलीं, राज्यों को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन सच यह है कि धरातल पर प्रगति के आकलन के लिए मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआइ) बनाते हुए विकास की कसौटी पर परखा तो देश की एक भी पंचायत पूरी तरह खरी नहीं उतरी। ए प्लस श्रेणी में कोई पंचायत नहीं है, जबकि ए श्रेणी में भी सिर्फ 12 राज्य खाता खोल सके हैं। उनकी कुल 699 पंचायतें इसमें स्थान बना सकी हैं। सर्वाधिक 61.2 प्रतिशत पंचायतें सी श्रेणी की हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ग्राम पंचायतों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड है। अपनी ग्राम पंचायतों को लेकर राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ कमियों को चिन्हित कर सुधारा जा सके, इसलिए पंचायतीराज मंत्रालय ने पहली बार इस तहर ग्रेडिंग की व्यवस्था शुरू की है। पहली रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के डाटा के आधार पर तैयार की गई है। देश की सभी 255699 ग्राम पंचायतों ने पीएआइ पोर्टल पर नौ थीम के संदर्भ में अपना डाटा अपलोड किया। चूंकि, मंत्रालय ने ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक और जिला के बाद राज्य स्तर पर भी आंकड़ों के सत्यापन की व्यवस्था बनाई थी, इसलिए राज्यों द्वारा सत्यापित 216285 ग्राम पंचायतों के डाटा को ही रिपोर्ट में शामिल कर आकलन किया। मेघालय, नगालैंड, गोवा, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल का डाटा राज्य स्तर पर सत्यापित न किए जाने के कारण इसमें शामिल नहीं हो सका। बहरहाल, प्राप्त डाटा का गहन परीक्षण करते हुए मंत्रालय ने अंकों के आधार पर पांच श्रेणियां बनाईं। ए प्लस (90 से 100 अंक), ए (75 से 90 अंक), बी (60 से 75 अंक), सी (40 से 60 अंक) और डी (40 अंक से नीचे)। स्थिति यह है कि ए प्लस श्रेणी में देश की एक भी ग्राम पंचायत अपना स्थान नहीं बना सकी। ए श्रेणी में कुल 699 पंचायतें (0.3 प्रतिशत) पंचायतें रही हैं। इनमें सर्वाधिक 346 पंचायतें गुजरात की हैं, दूसरे पर 270 तेलंगाना, तीसरे पर 42 त्रिपुरा, चौथे पर 12 दादरा एवं नगर हवेली व दमन-द्वीव, आठ-आठ पंचायतें केरल व महाराष्ट्र की तो चार पंचायतें उत्तर प्रदेश की हैं। यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इस श्रेणी में 31.5 प्रतिशत के साथ दादरा एवं नगर हवेली व दमन-द्वीव पहले पर है। 3.57 प्रतिशत पंचायतें त्रिपुरा, 2.11 प्रतिशत तेलंगाना तो 2.3 प्रतिशत पंचायतें गुजरात की हैं। उल्लेखनीय है कि जब पंचायत डिवाल्यूशन इंडेक्स जारी हुआ था तो इस रिपोर्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले ही अधिकतर राज्य उस रिपोर्ट की शीर्ष श्रेणी में शामिल थे। संकेत साफ है कि राज्यों ने पंचायतों को अधिकार हस्तांतरित किए तो वह बेहतर विकास के रूप में परिलक्षित भी हुआ।

सतत विकास लक्ष्यों की नौ थीम

1. पंचायत में गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका
2. स्वस्थ पंचायत 3. बाल अनुकूल पंचायत
4. जल पर्याप्त पंचायत
5. स्वच्छ एवं हरित पंचायत 6. आत्मनिर्भर बुनियादी सुविधाओं वाली पंचायत
7. सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित पंचायत 8. सुशासन वाली पंचायत
9. महिला अनुकूल पंचायत

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन नागौर यूनिट की जिला स्तरीय आमसभा संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नागौर । जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों का जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन जिला यूनिट नागौर की जिला स्तरीय आमसभा आज बलदेवाराम मिर्धा धर्मशाला नागौर में जिला अध्यक्ष भंवराराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई । इसमें एजेंडा अनुसार एरियर ब्याज के आंकड़े व्यवस्थापक द्वारा तैयार कर समिति बचत खाते में समायोजन करवाने, अवधिपार ऋण की वसूली पर देय 2 प्रतिशत ब्याज मार्जिन का समायोजन करने और शाखा स्तर पर यूनियन का बचत खाता खुलवाने के विषय पर चर्चा की गई । साथ ही, यूनियन में प्रत्येक शाखा की दो समितियों के अध्यक्षों को शामिल कर नई रणनीति बनाकर यूनियन को मजबूती देने पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ । इसके अलावा, नागौर एवं डीडवाना कुचामन जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सैल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सोसायटी अध्यक्षों का एक सामूहिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया । वही, कार्यकारिणी में बदलवा कर महासचिव का पद राजेन्द्र जाखड़ के स्थान पर मुकनाराम मकराना एवं सुरेंद्र कुमार के स्थान पर राजाराम कुमावत को नियुक्त करने के साथ-साथ प्रवक्ता अर्जुन राम टांडी एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर ओमप्रकाश कड़वासरा को निर्वाचित किया गया हैं । इस दौरान जिलेभर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहें ।

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर (जिला-जालोर) मंगलवार 15 अप्रैल 2025

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136

Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

जोधपुर खंड में 1546 ग्राम सेवा सहकारी समितियों वितरित करेगी अल्पकालीन फसली ऋण योजना

किसानों को ब्याज मुक्त योजना के तहत खरीफ सीजन में मिलेगा 3 हजार करोड़ का फसली सहकारी ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । खंड में 1546 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से इस खरीफ सीजन के दौरान ब्याज मुक्त योजना के तहत फसली सहकारी ऋण बांटने की कवायद शुरु हो गई हैं, प्रदेश में सीसीबीवार खरीफ सीजन में ऋण वितरण करने के लक्ष्य राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से आवंटन होने के पश्चात खंड में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े 7 लाख 75 हजार 829 किसानों को राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत 3000 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए किसान सदस्य को भी ऋण वितरण करने की कवायद शुरु की जाएगी । जोधपुर खंड में सर्वाधिक बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 3 लाख 10 हजार 761 किसानों को 945 करोड़ का फसली ऋण, इसी प्रकार जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 1 लाख 27 हजार 262 किसानों को 673 करोड़ का फसली ऋण, वही पाली केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 1 लाख 7 हजार 254 किसानों को 500 करोड़ का फसली ऋण इसके अलावा जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 1 लाख 34 हजार 131 किसानों को 379 करोड़ तथा जैसलमेर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 62 हजार 762 किसानों को 330 करोड़ एवं सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 33 हजार 659 किसानों को 146 करोड़ का फसली ऋण बांटने का लक्ष्य राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा 3 अप्रैल को ही तय कर दिया गया था । गौरतलब हैं कि किसानों को वितरित होने वाले फसली ऋणों का निर्धारित तिथि पर चुकारा होने पर संबंधित संस्थाओं को ब्याज अनुदान के रुप में केंद्र सरकार से 3 प्रतिशत तथा राज्य सरकार से 4 प्रतिशत राशि वहन की जाती है।

सावधिर ग्राम सेवा सहकारी समिति । फाइल

फैक्ट फाइल

बैंक	किसान	लक्ष्य
बाड़मेर सीसीबी	3 लाख 10 हजार किसान	945 करोड़
जोधपुर सीसीबी	1 लाख 27 हजार किसान	673 करोड़
पाली सीसीबी	1 लाख 7 हजार किसान	500 करोड़
जालोर सीसीबी	1 लाख 34 हजार किसान	379 करोड़
जैसलमेर सीसीबी	62 हजार 762 किसान	330 करोड़
सिरोही सीसीबी	33 हजार 659 किसान	146 करोड़

सहकारिता विभाग के खंडीय कार्यालय जोधपुर खंड में खरीफ सीजन के दौरान सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 1546 ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े 7 लाख 75 हजार 829 किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त योजना के तहत 3000 करोड़ का फसली सहकारी ऋण

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

सहकारिता विभाग के जोधपुर खंडीय कार्यालय के अधीन छह केंद्रीय सहकारी बैंक संचालित हैं, इनके कार्यक्षेत्र में 1546 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यशील हैं, नए ऋण लेने के लिए संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को नए सदस्य बनने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित किसान को खेत की जमाबंदी, बैंक पासबुक व जनाधार कार्ड प्रस्तुत करने पर आवदेक किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से नया लोन स्वीकृत किया जाएगा।

साहूकारों के चंगुल से मिलेगी निजात

जोधपुर खंड में रबी सीजन की तुलना में खरीफ सीजन में खेती करने वाले किसानों की संख्या ज्यादा होती है।

खरीफ सीजन में असिंचित क्षेत्र में भी बुवाई की जाती है। खरीफ सीजन की बुवाई करने के लिए कई बार किसान को अपनी उपज औने-पौने दामों में साहूकारों को बेचनी पड़ती है। केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा खरीफ सीजन में सदस्य किसान को ब्याज मुक्त ऋण देने से वे साहूकारों के चंगुल में फंसने से बच जाएंगे।

हनुमानसिंह राजावत, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन

सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जारी हुआ ऋण वितरण का लक्ष्य

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के दौरान समेकित आधार पर ढाई लाख पात्र गोपालक परिवारों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की बजट घोषणा के तहत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक संजय पाठक की ओर से प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को एक आदेश जारी कर लक्ष्यों का आवंटन करते हुए बताया गया हैं कि यह लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपात में ही आवंटित किए गए हैं।

सीसीबी	–	लक्ष्य
जयपुर	–	21 हजार 115
बाड़मेर	–	20 हजार 705
भीलवाड़ा	–	11 हजार 845
अलवर	–	10 हजार 895
बूंदी	–	11 हजार 845
हनुमानगढ़	–	10 हजार 715
झालवाड़	–	10 हजार 625
नागौर	–	10 हजार 610
सीकर	–	10 हजार 120
बीकानेर	–	9 हजार 775
जालोर	–	9 हजार 530
श्रीगंगानगर	–	9 हजार 435
सवाई माधोपुर	–	9 हजार 165
झुंझुनूं सीसीबी	–	8 हजार 165
जोधपुर	–	7 हजार 760
उदयपुर	–	7 हजार 640
टोंक	–	7 हजार 290
चूरू	–	7 हजार 010
अजमेर	–	6 हजार 850
पाली	–	6 हजार 610
कोटा	–	6 हजार 160
दौसा	–	6 हजार 115
भरतपुर	–	6 हजार 025
बांसवाड़ा	–	4 हजार 775
डूंगरपुर	–	4 हजार 120
बारां	–	4 हजार 115
जैसलमेर	–	3 हजार 295
सिरोही	–	2 हजार 170

कारुण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक पर की जा रही कार्यवाहियों का दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग

सहकारिता मंत्री को पत्र लिखकर भाजपा मंडल महामंत्री ने नियमानुसार निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

भाजपा पश्चिमी मण्डल महामंत्री ने सहकारिता मंत्री को पत्र लिखकर सहकारिता विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी से संपूर्ण प्रकरण की दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों की सजा दिलाने और जांच पूर्ण होने तक जयदेव देवल तत्कालीन उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ और नानालाल चावला तत्कालीन प्रबंध निदेशक सीसीबी चित्तौड़गढ़ को ए.पी.ओ करने की उठाई मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर । प्रदेश के निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पश्चिमी मण्डल महामंत्री राजेश जैन ने सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को चित्तौड़गढ़ जिले में सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा कारुण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक यानि उनके पिता पर की जा रही कार्यवाहियों का दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाने और व्यवस्थापक को वेतन सहित सेवानिवृत्ती परिलाभों का भुगतान करवाने की मांग उठाई हैं । भाजपा पश्चिमी मण्डल महामंत्री राजेश जैन की ओर से सहकारिता मंत्री को भेजे गए पत्र के मुताबिक, कारुण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक को सूचित किए बिना ही उनकी अनुपस्थिति में अपूर्ण रिकार्ड का अंकेक्षण करवाकर 67 लाख से ज्यादा की राशि का गबन प्रकरण विभागीय कोर्ट में दर्ज कराया गया, वही चित्तौड़गढ़ सीसीबी प्रबंध निदेशक द्वारा पुलिस थाना सदर में गबन का प्रकरण दर्ज कराया गया । जबकि व्यवस्थापक द्वारा विभागीय जांच में पूर्ण सहयोग किया जा रहा था । साथ ही, पत्र में बताया गया हैं कि लगभग 4 साल विभागीय जांच एवं 2 साल पुलिस की जांच चलने के उपरांत व्यवस्थापक को निर्दोष साबित किया गया । वही, व्यवस्थापक द्वारा सहकारिता विभाग के सात अधिकारियों पर पुलिस थाना सदर में दर्ज कराया गया प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन का उल्लेख पत्र में करते हुए भाजपा मंडल महामंत्री ने बताया कि 16 मार्च 2022 को जांच पूर्ण होने एवं निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में प्रकरण प्रक्रियाधीन के साथ-साथ पुलिस जांच में एफ आर लगने के बावजूद उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ द्वारा आधारहीन जांच शुरु की गई, जिसको मात्र 4 माह में ही खत्म कर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 57(1) एवं 57(2) का निर्णय जारी कर दिया गया । जिसमें, जयदेव देवल तत्कालीन उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ एवं नानालाल चावला तत्कालीन प्रबंध निदेशक सीसीबी चित्तौड़गढ़ द्वारा फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए राजेश जैन ने बताया कि जांच के लिए उप रजिस्ट्रार द्वारा 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया गया हैं, जिसकी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगने पर आदेश जारी नहीं होने की जानकारी देने का हवाला भी पत्र में दिया गया है।

नरेगा श्रमिकों का समय जिला कलेक्टर कर सकेंगे निर्धारित

जयपुर। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत श्रमिक समूह 8 घंटे की कार्य अवधि 1 घंटे के विश्राम काल के साथ निश्चित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए योजना अंतर्गत कार्यों का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर निर्धारित कर सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि कार्य समय इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि कार्य की अवधि 8 घंटे 1 घंटे के विश्राम के साथ हो। विश्राम काल का प्रावधान नहीं रखने की स्थिति में 7 घंटे की कार्य अवधि की जा सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जिला स्तर पर इस संबंध में निर्देश जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जा सकता है कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पहले निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूरा कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल के टास्क प्रपत्र में अंकित करवाने के उपरांत समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के बाद कार्य स्थल छोड़ सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

चूण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चूण्डा

International Year of Cooperatives — Cooperatives Build a Better World

एक सब के लिए सब एक के लिए

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

दिनेश कुमार — व्यवस्थापक

प्रेम सिंह — अध्यक्ष

हनुवन्त सिंह — उपाध्यक्ष

पता राम — सहा. व्यवस्थापक

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब '

ब्याज मुक्त योजना से अधिकाधिक लाभान्वित हो किसान - सीसीबी प्रबंध निदेशक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । केंद्रीय सहकारी बैंक की धुम्बड़िया शाखा में आज सीसीबी प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा शाखा कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समस्त व्यवस्थापकों की एक संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें प्रबंध निदेशक नारायणसिंह द्वारा राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना में निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति कर अधिकाधिक किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित कर लाभांवित करने के साथ खरीफ सीजन में वितरित ऋण एवं अवधिपार ऋणों की समयबद्धता से वसूली करने और केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना को प्राथमिकता देने सहित राज्य सरकार की राजस्थान सहकार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पात्र गोपालकों को लाभान्वित करने तथा कॉमन सर्विस सेन्टर, जन औषधि केंद्र, खाद-बीज का लाभ भी किसानों को देने के निर्देश दिए गए । साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यवसाय विविधिकरण को बढ़ावा देने और भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय जैविक सहकारी संगठन की सदस्यता लेने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों का ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान धुम्बड़िया शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार, ऋण पर्यवेक्षक डायाराम देवासी, बागोड़ा व्यवस्थापक रमेश कुमार, चैनपुरा व्यवस्थापक वेणीदान चारण सहित समस्त सहकारी समितियो के व्यवस्थापक उपस्थित रहें।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 9 मई से शुरु, सहकारी संस्थाओं से अंशदान राशि की अपील

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। इस वर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन 9 मई से 18 मई तक जयपुर में किया जाएगा। इस वार्षिक मेले में विभिन्न सहकारी संस्थाएं भाग लेकर अपने उत्पादों की बिक्री और योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएंगी। सहकारिता के प्रचार-प्रसार के लिए यह मेला एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। इस मेले का आयोजन स्व-वित्त पोषण के आधार पर किया जाता है। आयोजन के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं से निर्धारित अंशदान राशि की अपील की गई है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, इफको, राजपीड, जिला सहकारी दुग्ध संघ, और अन्य सहकारी संस्थाओं से योगदान राशि देने का अनुरोध किया गया है। संस्थाओं से आग्रह किया गया है कि वे सात दिनों के भीतर उपहार कोष, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. के नाम पर निर्धारित राशि जमा करें। इस आयोजन का उद्देश्य सहकारी संगठनों के उत्पादों को बढ़ावा देना और सहकारिता के विचार को सशक्त करना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन को सुगम और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को दस लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में यह योजना शुरु की गई थी। इस योजना के अंतर्गत तीन श्रेणियों के ऋण दिए जा रहे हैं। इसमें 50 हजार रुपये तक का शिशु, पांच लाख रुपये तक का किशोर और दस लाख रुपये तक का तरुण ऋण शामिल है। लगभग 70 प्रतिशत मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों ने लिए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है। 50 प्रतिशत से अधिक मुद्रा ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा योजना ने भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य को नया रूप दिया है और वित्तीय समावेशन के एक मॉडल के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त की है।

पानी की दरों में वृद्धि का भार उठाएगी राज्य सरकार

जयपुर,। प्रदेश में पेयजल की दरों में वृद्धि का अतिरिक्त भार जनता पर नहीं डालने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। अब पेयजल उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों एवं अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में शेष राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है इससे सरकार पर लगभग 2100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आएगा। जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल ने बताया कि विभाग के माध्यम से आम जनता को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2017 से लागू पानी की दरों में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि नहीं की गई है। जलदाय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेयजल की दरों को वास्तविक लागत के आधार पर तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है।

अतिरिक्त अधिषासी अधिकारी ने पैक्स कप्यूटरीकरण को गति देने के दिए निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले की केंद्रीय सहकारी बैंक की जसंवतपुरा शाखा अंतर्गत संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की एक बैठक का आयोजन किया गया । इसमें सीसीबी प्रबंध निदेशक नारायणसिंह के निर्देशन पर अतिरिक्त अधिषासी अधिकारी सुभाष चंद्र ने राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली करने और पैक्स कम्प्यूटरीकरण को गति देने, कॉमन सर्विस सेन्टर, जन औषधि केंद्र, खाद-बीज सहित सहकारी समितियों में व्यवसाय विविधिकरण को बढ़ावा देने तथा भारतीय बीज सहकारी समिति एवं राष्ट्रीय जैविक सहकारी संगठन की सदस्यता लेने एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों का ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इस दौरान जसवंतपुरा शाखा प्रबंधक हंसराज मीणा व बैंकिंग स्टाफ सहित समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक उपस्थित रहें ।

किसानों को समर्थन मूल्य योजना का अधिकाधिक लाभ दिया जावे - संयुक्त शासन सचिव

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर,। राजीव गांधी सहकार भवन, जोधपुर में वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद एवं सहकारिता विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु एक अहम बैठक का आयोजन सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में किया गया । जिसमे संयुक्त शासन सचिव ने निर्देशित किया कि किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी एक टीम भावना के साथ पूर्ण संवेदनशीलता से कार्य करें। सभी खरीद केन्द्रों पर किसानों को जागरूक करने के लिए बैनर और होर्डिंग्स लगाए जाएं, जिनमें समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को प्राप्त अधिकारों की जानकारी हो तथा समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित किए जाएं। संयुक्त शासन सचिव ने संभाग में उपलब्ध भंडारण सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि निजी गोदामों की भंडारण क्षमता का भी आंकलन किया जाए ताकि किसानों की उपज को सुरक्षित रखा जा सके और मौसमी क्षति से बचाया जा सके। खरीद में आवश्यक बारदानों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने खराब बारदानों की आपूर्ति की समस्या बताई, जिस पर उन्होंने नेफेड एवं एनसीसीएफ से संपर्क कर समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। संयुक्त शासन सचिव ने समर्थन मूल्य योजना में कम पंजीयन पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सहकारी समितियों के संचालकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर योजना को अधिक प्रभावी बनाया जाए। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु ट्रांसपोर्टेशन में GPS एवं जियो फेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाए। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों एवं इकाई अधिकारियों को फीडबैक हेतु प्रारूप उपलब्ध कराए गए ताकि उनके अनुभवों के आधार पर खरीद व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

फसली ऋण वितरण एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा

बैठक में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के फसली ऋण वितरण की समीक्षा की गई। जैसलमेर सीसीबी में कम ऋण वितरण पर चिंता व्यक्त करते हुए जिमेदार कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए। साथ ही 'सहकार से समृद्धि', पैक्स कप्यूटराइजेशन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सहकारी संस्थाओं की समय पर ऑडिट सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना का प्रचार

भूमि विकास बैंकों द्वारा सरकार की एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए ताकि अधिक से अधिक ऋणी किसान योजना का लाभ उठा सकें और बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो। संभाग के सहकारी उपभोक्ता भंडारों द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं सामग्रियों की दरों का प्रचार-प्रसार विभिन्न सरकारी कार्यालयों में करने के निर्देश दिए गए ताकि इनसे अधिकाधिक कार्यालय लाभान्वित हो सकें और भंडारों के व्यवसाय में वृद्धि हो।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

सिणेर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सिणेर

International Year of Cooperatives — Cooperatives Build a Better World

एक सब के लिए सब एक के लिए

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

नरसिंगाराम शर्मा — व्यवस्थापक

गणपतसिंह राठौड़ — अध्यक्ष

गुलाब सिंह — सहा. व्यवस्थापक

भंवर सिंह राठौड — उपाध्यक्ष

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब '

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।